

दैनिक

रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

चोरी के बाद होटल में टहरते बंटी बबली



मुंबई : अंधेरी पुलिस ने चोरी के बाद होटल में रहनेवाले बंटी-बबली को होटल में जाने से पहले गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने आरोपियों ने मिलकर एक व्यक्ति के गले से चैन खींचा और भाग गए थे। जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने 100 सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रहने के लिए होटल में जक यह थे तभी इन्हें पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। मामले कि अधिक जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सोनु शेख (26) और नीलम मून (36) है। दोनों कभी होटल कभी ऑटो और दूसरे जगहों पर रहकर अपना जीवन बिताते थे। अब पैसे के लिए इन्होंने चोरियां करनी शुरू कर दी।

मनपा ने भी शुरू किया मंदिर सफाई अभियान हर वार्ड की तीन मंदिरों की सफाई करने का आयुक्त का निर्देश

मुंबई : राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान को लेकर आयोध्या में चल रहे अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मुंबई मनपा भी मंदिरों का सफाई अभियान छेड़ दिया है। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मनपा के सभी सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र की तीन मंदिरों का सफाई करे। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मनपा के सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया है कि मुंबई में डीप क्लीनिंग चल रही है।



का निर्देश दिया। मनपा प्रशासन ने मुंबई क्षेत्र के मंदिर परिसर में 22 जनवरी तक जनभागीदारी और श्रमदान के माध्यम से गहन स्वच्छता अभियान करे इस तरह का निर्देश दिया है। मनपा आयुक्त ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रशासनिक प्रभाग में कम से कम तीन प्रमुख मंदिरों का चयन स्थानीय स्तर पर करना है और मंदिर परिसर की डीप क्लीनिंग के तहत पूरे परिसर को स्वच्छ करना है। मनपा प्रशासन ने स्वच्छता अभियान के लिए 61 बिंदुओं को शामिल करते हुए एक मानक प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की है जिसके तहत महास्वच्छता अभियान ह्य कर मंदिर परिसर को साफ करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने मंदिर की सघन स्वच्छता अभियान के तहत मंदिरों की साफ-सफाई और रोशनी करने का निर्देश दिया है।

सड़कों के कंक्रीटीकरण का

1362 करोड़ का टेंडर रद्द!

मुंबई : मुंबई में सड़कों को कंक्रीट करने के लिए बुलाए गए नए 1362 करोड़ के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। मुंबई नगर निगम की ओर से आज हाई कोर्ट में यह जानकारी दी गई। इस बीच, न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खट्टा की पीठ ने नगर पालिका को याचिकाकर्ता कंपनी की याचिका पर 31 जनवरी तक सुनवाई करने का निर्देश दिया। मेसर्स रोडवे सॉल्यूशंस इंफ्रा लिमिटेड (आरएसआईएल) को रुपये से अधिक का अनुबंध दिया गया है। हालांकि, नगर पालिका ने अनुबंध रद्द कर दिया और 4 दिसंबर को कंक्रीटिंग के लिए 1,362.34 करोड़ रुपये का नया टेंडर बुलाया।



नगर पालिका के इस फैसले के खिलाफ आरएसआईएल कंपनी हाई कोर्ट पहुंची और याचिका दायर की। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खट्टा की पीठ ने नगर पालिका के नये टेंडर पर अस्थायी रोक लगा दी। साथ ही नगर पालिका से इस संबंध में भी जानकारी मांगी गई कि याचिकाकर्ताओं का सवाल सुना जाया नहीं। नगर पालिका की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत थोराट और अधिवक्ता जोएल कार्लोस ने पीठ को बताया कि 1362.34 करोड़ रुपये के टेंडर रद्द कर दिये गये हैं। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उठाए गए सदेहों पर 31 जनवरी तक सुनवाई करने का निर्देश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया। नगर पालिका अब तक मुंबई में सड़कों के कंक्रीटिंग के टेंडर दो बार रद्द कर चुकी है।

वसई विरार पुलिसकर्मी 15 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार



वसई : वसई विरार पुलिसकर्मी ने रुपये की मांग की थी। इस रकम की पहली किस्त 15 लाख लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वित्तीय अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र शेलार फरार हो गए हैं। इस मामले में वादी के खिलाफ वित्त शाखा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र शेलार ने गिरफ्तारी से बचने और मदद पाने के लिए 50 लाख की मांग की थी। समझौते के बाद रकम 35 लाख तय हुई। इसके बाद वादी ने ठाणे के रिश्वत निरोधक

विभाग में शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले की जांच के बाद

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने पुलिस कमिश्नरेट में जाल बिछाया था। भायंदर पुलिस स्टेशन के कर्मचारी गणेश वनवे को रिश्वत की रकम की पहली किस्त पंद्रह लाख लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लेकिन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र शेलार फरार हो गये हैं। इस मामले में मीरा रोड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

150 रेलवे ट्रेनों में 300 आधिकारिक फेरीवाले, 32 लाख का राजस्व!

मुंबई : मध्य रेलवे ने उपनगरीय लोकल और मेल-एक्सप्रेस में अधिकृत फेरीवालों को नियुक्त करने का निर्णय लिया था। सेंट्रल रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि अब सेंट्रल रेलवे ने 150 मेल-एक्सप्रेस में 300 आधिकारिक फेरीवालों की नियुक्ति के लिए एक ठेकेदार को नियुक्त किया है। उपनगरीय लोकल सेवाओं और मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में अवैध फेरीवालों की बढ़ती संख्या के बारे में यात्रियों की शिकायतें थीं। इसलिए



सेंट्रल रेलवे ने इन अवैध फेरीवालों पर लगाम लगाने के लिए अपने यहां आधिकारिक फेरीवालों को नियुक्त करने का फैसला किया।

कचरे की दुर्गंध से उरण के नागरिक परेशान

उरण : शहर के मध्य में स्थित विमला झील में नागरिक अक्सर व्यायाम और मनोरंजन के लिए आते हैं, लेकिन झील में कचरे से दुर्गंध आने लगी है। इसका खामियाजा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए, यह सवाल उठ रहा है कि उरण का विमला झील विश्राम स्थल है या नगर परिषद का कूड़ाघर। नगर परिषद का



विमला तालाब उरण जैसे शहर के मध्य में स्थित है। इस झील में बगीचे, बच्चों के खिलौने और वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, बैठने की व्यवस्था के कारण प्रतिदिन इस झील पर आने

वाले नागरिकों की संख्या बहुत अधिक है। इस झील पर सुबह 5 बजे से ही नागरिकों का तांता लग जाता है। यह रात 9 बजे तक है। शाम के समय यह स्थान शहर के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। उरण नगर परिषद के माध्यम से इस झील में कई सुविधाएं बनाई गई हैं। लेकिन झील पर आने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

झील में अनेक असुविधाएँ हैं। यहां की बेंचें टूटी हुई हैं। इससे बैठने में असुविधा हो रही है। दूसरी ओर निर्मात्य को उसी तालाब में बहाया जा रहा है। अनेक नागरिक अपने घरों में निर्मात्य ला रहे हैं। इसी प्रकार झील में लगातार पानी जमा होने तथा झील में कूड़ा-कचरा सड़ने से झील के पानी में दुर्गंध उत्पन्न हो रही है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आने वाले नागरिकों को इस झील की दुर्गंध से परेशानी हो रही है।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

कश्मीर की देशज दृष्टि

पिछले कुछ वर्षों से भारत अपनी पहचान और यथार्थ को लेकर अधिक संवेदनशील हुआ है। इस कारण देशज उपकरणों और शब्दावली के माध्यम से भारतीय यथार्थ को समझने की व्यग्रता बढ़ी है। यह व्यग्रता औपनिवेशिक आधिपत्य वाले विमर्श की सीमाओं और क्षुद्रताओं को तो उजागर कर ही रही है, भारतीय हितों, संघर्षों और अंतर्द्वंद्वों को न सिरे से परखने की

कोशिश भी कर रही है। इस कोशिश में सबसे प्रमुखता के साथ जो तथ्य उभरकर सामने आता है, वह यह है कि सैकड़ों सालों का मजहबी और औपनिवेशिक बोझ भारतीय पहचान के प्रति आकर्षण कम नहीं कर सका है। और यह भी कि मजहबी और औपनिवेशिक खांचों में फंसा भारतीय हिस्सा भी अब यह समझने लगा है कि उसके हितों और पहचान का अभिकेन्द्र कहीं बाहर नहीं बल्कि भारत और भारतीयता ही है। जम्मू-कश्मीर के ख्यातिलब्ध विद्वान और प्रसिद्ध भारतविद प्रो. कुलदीप चंद अग्निहोत्री की नई पुस्तक ह्यकश्मीर का रिसता घाव : एटीएम बनाम डीएम का संघर्ष मुसलमानों के भारतीय यथार्थ को नई शब्दावली और उपकरणों के माध्यम से समझने की एक ऐसी ही कोशिश है। प्रो. अग्निहोत्री ने भारतीय मुसलमानों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभक्त कर मुसलमानों की आंतरिक दुनिया में झांकने की कोशिश की है। वह विदेशी नस्ल के मुसलमानों को एटीएम (अरब-तुर्क-मुगल) कहते हैं और भारतीय मूल के मुसलमानों को डीएम (देशी मुसलमान) के नाम से संबोधित करते हैं। इस शब्दावली के माध्यम से उन्होंने मोटे तौर पर सम्पूर्ण भारत और विशेष रूप में जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों की सामाजिक-सांस्कृतिक गत्यात्मकता को समझने की कोशिश की है।

उनका मानना है कि मुसलमानों को एक समूह और एटीएम को मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने से राजनीतिक और अकादमिक स्तर पर मुसलमानों की वास्तविक स्थिति देश के सामने नहीं आ पाई है। इस न्यूनता के कारण जहां साम्प्रदायिक संघर्षों की प्रकृति को समझने में नीति नियंता प्रायः विफल हो जाते हैं और आर्थिक स्तर पर लक्षित समूहों तक योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है और न ही उनके सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठ पाते हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि एटीएम को मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने से देशज मुसलमानों को उनकी भारतीय संबद्धता से एकदम से काटने के प्रयास किए जाते हैं। वह कहते हैं, जब भी भारत में मुसलमानों का अध्ययन किया जाता है तो एटीएम बनाम डीएम को जोड़कर भारतीय मुसलमान कह दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार के अध्ययनों में केस स्टडी के लिए एटीएम को ही लिया जाता है, लेकिन उसके निष्कर्षों से डीएम या देसी मुसलमानों को शिकार बनाया जाता है। इस प्रकारा देसी मुसलमान एटीएम के नीचे दब जाता है। उनका मानना है कि जम्मू-कश्मीर का प्रश्न हिन्दू-मुस्लिम से अधिक एटीएम बनाम डीएम का प्रश्न है। यदि इस संघर्ष के कारणों और उपकरणों की ठीक ढंग से पहचान कर ली जाए तो जम्मू-कश्मीर के प्रश्न के समाधान में तो सहयोग मिलेगा ही, सम्पूर्ण भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। इस पुस्तक में इन दोनों समुदायों के टकराव, उसके विविध पड़ावों, उसमें अपनाई जाने वाली रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है। टकराव का मुख्य बिंदु यह है कि विदेशी मुसलमानों का वर्ग देशी मुसलमानों से उनकी प्रत्येक पहचान को छीनकर अपने खांचे में ढालने के लिए प्रयास करता है।

+91 99877 75650

editor@rokhoklekhaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

सुशील कुमार शिंदे और उनकी बेटी को बीजेपी में शामिल होने की कोई पेशकश नहीं की गई - बावनकुले

मुंबई: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें और उनकी विधायक बेटी परिणीति शिंदे को बीजेपी में शामिल होने का न्योता मिला था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हैं और अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। शिंदे ने यह दावा मंगलवार को सोलापुर जिले के अक्कलकोट तहसील में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया। हालांकि, बीजेपी का कहना है कि शिंदे और उनकी बेटी को पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पेशकश नहीं की गई है।

सुशील कुमार शिंदे ने कहा, "परिणीति ताई और मुझे बीजेपी की

ओर से पेशकश की गई लेकिन यह कैसे (पार्टी बदलने के संदर्भ में) संभव है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई है और यह कैसे संभव है कि किसी दूरसे के घर में जाऊं। मैं कभी दल-बदल में नहीं पड़ा।" कार्यक्रम के बाद जब संवाददाताओं ने शिंदे से पूछा कि उन्हें किसने बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की तो उन्होंने उनका नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि

जिस व्यक्ति ने पेशकश की, वह एक 'बड़ा' आदमी है।

सुशील कुमार शिंदे ने कहा, "मैंने कहा कि मैं निष्ठावान कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।" शिंदे के दावे का खंडन करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक समाचार चैनल से कहा कि शिंदे और उनकी बेटी को बीजेपी में शामिल होने की कोई

पेशकश नहीं की गई है। इस बीच, राज्य सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने सोलापुर शहर में शिंदे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। पाटिल सोलापुर के प्रभारी मंत्री भी हैं।

सूत्रों ने बताया कि पाटिल की शिंदे से मुलाकात आगामी साहित्य सम्मेलन के लिए न्योता देने की खातिर थी। सुशील कुमार शिंदे 2003 से 2004 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) शासन के दौरान वह ऊर्जा और गृह मंत्री थे। उनकी बेटी परिणीति तीसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य हैं। वह सोलापुर मध्य सीट से विधायक हैं।



महाराष्ट्र में कोविड-19 के 81 मामले आए, एक की मौत



मुंबई: महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 के 81 नए मामले आए और संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि वायरस के जेएन.1 उपस्वरूप से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 451 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि संक्रमण से पुणे शहर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोविड-19 से मृत्यु दर वर्तमान में 1.81 प्रतिशत है। मुंबई में कोविड-19 के 26 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में ओमीक्रॉन के जेएन.1 उपस्वरूप से संक्रमित रोगियों की संख्या

सबसे अधिक पुणे (189) में है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पुणे के बाद ठाणे में जेएन.1 उपस्वरूप के 89 मामले सामने आए हैं जबकि मुंबई में 37, छत्रपति संभाजी नगर में 31, नागपुर में 30 मामले आए हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को 97 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में संक्रमण से उबरने की दर 98.18 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,269 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 1,783 नमूनों की जांच आरटी-पीसीआर से और 10,486 नमूनों की जांच रेपिड एंटीजन टेस्ट से की गई।

मोदी 19 जनवरी को महाराष्ट्र में आठ 'अमृत' परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे



मुंबई: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गयी है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि दक्षिणी महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में सुबह करीब पौने 11 बजे आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वह राज्य में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की आठ अमृत (अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें कहा गया है कि वह प्रधानमंत्री आवास

योजना (शहरी) के तहत निर्मित 90,000 से अधिक आवासों को लाभार्थियों को समर्पित करेंगे।

इसके अलावा प्रधानमंत्री सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 आवासों को भी लोगों को समर्पित करेंगे जिनके लाभार्थियों में हजारों हथकरघा श्रमिक, विक्रेता, पावरलूम श्रमिक, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी श्रमिक और चालक शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मोदी महाराष्ट्र में पीएम-स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त के वितरण की शुरुआत भी करेंगे।

महज पांच दिनों में 1 लाख 32 हजार यात्रियों ने किया दीघा स्टेशन पर सफर

ठाणे: ट्रांस हार्बर रूट पर ऐरोली और ठाणे रेलवे स्टेशनों के बीच बने दीघा गाँव रेलवे स्टेशन से पांच दिनों में 1 लाख 32 हजार 871 यात्रियों ने यात्रा की। मंगलवार को यात्रियों की संख्या 63 हजार से ज्यादा थी। ऐसे में यात्रियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पांच दिनों में सेंट्रल रेलवे को इस स्टेशन से 6 लाख 38 हजार 520 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। दीघा गाँव स्टेशन के

निर्माण के कारण, ठाणे और ऐरोली रेलवे स्टेशनों पर उत्पन्न यात्री भार भी कुछ हद तक हल्का हो गया है। नवी मुंबई शहर के दीघा क्षेत्र, ऐरोली, रबाले और घनसोली क्षेत्र में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय शुरू हो गए हैं। इसलिए, ठाणे, कल्याण, कर्जत, कसारा, मुलुंड, भांडुप क्षेत्रों से यात्रा करने वाले लाखों यात्री ठाणे स्टेशन से ट्रांस हार्बर के माध्यम से नवी मुंबई



जा रहे हैं। साथ ही नवी मुंबई के ऐरोली और दीघा इलाके में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले, दीघा गाँव स्टेशन नहीं होने के कारण, दीघा, विटवा, कलवा क्षेत्रों के यात्रियों को ऐरोली या ठाणे रेलवे स्टेशन से यात्रा करनी पड़ती थी।

'अटल सेतु' न्हावा शेवा-शिवाडी ब्रिज के जसाई में भूमि अधिग्रहण रद्द।

मुंबई: "अटल सेतु" न्हावा शेवा शिवाडी ब्रिज। यह 21.8 किमी लंबा 6 लेन सड़क पुल है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। यह पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह महाराष्ट्र सरकार, सिडको और एमएमआरडीए की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हाल ही में इस पुल का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 12 जनवरी को...लेकिन वही "अटल सेतु" अब विवादों के भंवर में फंसने जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अधिनियम के तहत अधिसूचना 2009 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 2012 में प्रकाशित की गई थी। इस बीच केंद्र में "नया भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम 2013" पारित किया गया था। यह अधिनियम किसानों के लिए एक वरदान था। चार बाजार मूल्य से कई गुना नकद और विकसित भूखंडों का 20% और अन्य। पुनर्वास के कई लाभ प्रदान करते हुए, सिडको और

उप-जिला अधिकारी मेट्रो केंद्र उरण ने पुरस्कार की घोषणा करके केवल 50 हजार रुपये प्रति कड़्हा की दर तय करके किसानों को धोखा दिया। पुराने 1894 के कानून के अनुसार।

उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय लेते समय दो वर्ष की अवधि के अंदर जानकारी नहीं देने के कारण तकनीकी रूप से भूमि अधिग्रहण रद्द किया जा रहा है। यह बात चिरले गांव के किसान संदेश ठाकुर और अधिवक्ता राहुल ठाकुर ने बताईं। अधिवक्ता संकेत



ठाकुर, अधिवक्ता सुष्मिता भोईर। इसी सूत्र को पकड़ते हुए, चिरले गांव के निवासी संदेश विठ्ठल ठाकुर, जो मौजे जसाई की जमीन के मालिक हैं, ने 25 भूस्वामियों के साथ कुल 7 हेक्टेयर और 13 गुंटा जमीन के फैसले को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जो कि 1894 अधिनियम के तहत रद्द किया जा रहा था, और 2017 को, वकील एडवोकेट। राहुल ठाकुर के माध्यम से एक रिट याचिका दायर की गई थी। और लगभग 6 साल की अदालती लड़ाई के बाद, उक्त याचिका पर अंतिम सुनवाई

9 अक्टूबर, 2023 को न्यायमूर्ति कुलबावाला और न्यायमूर्ति साठे की पीठ द्वारा की गई और 22 अप्रैल, 2015 को भूमि अधिग्रहण पुरस्कार को अमान्य और अवैध मानते हुए मुहर लगा दी गई। 16 जनवरी 2024 को फैसला सुनाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो याचिकाकर्ता किसान अदालत में गए थे और जिन्हें प्रति भूखंड 50,000 रुपये का भुगतान किया गया था, उनकी भूमि को "नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013" के तहत अधिग्रहित किया जाना चाहिए, भूमि मालिकों को दोगुना मुआवजा दिया

जस्टिस कुलाबावाला और जस्टिस साठे ने किसानों के पक्ष में सुनाया फैसला:

बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच के फैसले के अनुसार कोई भी भूमि अधिग्रहण 1894 के पुराने अधिनियम के तहत शुरू हुआ था जो 2013 के नए अधिनियम के शुरू होने तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसे सभी मामलों में 2013 के अधिनियम के तहत 4 गुना मुआवजे को मंजूरी देकर पुरस्कार की घोषणा की जानी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि 2013 के नए कानून के अनुसार, सभी भूमि अधिग्रहण पुरस्कारों की घोषणा 20 मार्च 2015 से पहले की जानी थी और इसलिए भूमि मालिक संदेश ठाकुर और नवी मुंबई के वकील एडवोकेट।

जाना चाहिए। 2024 का बाजार मूल्य और 100% मुआवजा यानी जमीन के बाजार मूल्य का 4 गुना। यानी 40 से 50 लाख प्रति यूनिट देना होगा। साथ ही 20% विकसित प्लॉट देने होंगे और पुनर्विकास के अन्य लाभ भी देने होंगे दिया जा।

भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल के लिए भूमि अधिग्रहण में इन गलतियों के कारण सीलिक के निर्माण में अग्रणी सिडको और एमएमआरडीए को भारी झटका लगा है। सिडको को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह पुरस्कार अमान्य, अवैध है।

खिचड़ी घोटाले केस में ED की बड़ी कार्रवाई!

उद्धव गुट के नेता सूरज चव्हाण गिरफ्तार



मुंबई: "प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को शिवसेना के उद्धव गुट (यूबीटी) नेता सूरज चव्हाण को कोविड-19 के दौरान प्रवासियों को खिचड़ी के वितरण में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ के बाद चव्हाण को देर शाम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद है कि गुरुवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।

चव्हाण पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का सहयोगी होने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एक एफआईआर से उपजा है। पुलिस के अनुसार, कोविड-19 संकट के दौरान प्रवासियों को खिचड़ी उपलब्ध

कराने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा ठेका देते समय कथित अनियमितताएं हुईं। महाराष्ट्र में कठोर गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय! जानें किस पार्टी को मिल सकती है सबसे अधिक सीटें सूत्रों के मुताबिक, आरोप है कि सूरज चव्हाण ने चुनिंदा ठेकेदारों को ठेके देने के लिए बीएमसी अधिकारियों को प्रभावित किया था, जिनका पार्टी

नेताओं से कथित तौर पर सीधा संबंध था। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सितंबर 2023 में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर, सुनील उर्फ बाला कदम, स'द्रि रिफ्रेशमेंट के राजीव सालुंके और अन्य के खिलाफ खिचड़ी घोटाले के संबंध में मामला दर्ज किया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक, खिचड़ी वितरण का ठेका देने में करीब 6.37 करोड़ रुपये की अनियमितता होने का अनुमान है। आरोपों के अनुसार, आरोपी ने प्रस्तुत चालान के अनुसार उल्लिखित नंबरों पर खिचड़ी की आपूर्ति नहीं की। साथ ही खाने के पैकेट 250 ग्राम के होने चाहिए थे, लेकिन ठेकेदारों ने उन पैकेटों में सिर्फ 125 ग्राम खाना ही बांटा।

'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में शामिल होने के लिए प्रकाश आंबेडकर को मिला न्योता

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 10 साल के शासन को 'अन्याय काल' करार देते हुए कांग्रेस ने मणिपुर के थौबल जिले से 66 दिवसीय 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' शुरू की है। यह यात्रा 15 राज्यों से होकर 6,713 किमी की दूरी तय करने के बाद 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने थौबल जिले के खोंगजोम युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह स्मारक 1891 में अंतिम एंग्लो-मणिपुर युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्इअ अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर को भी न्योता मिला है। अब वो शामिल होंगे या नहीं इसपर सस्पेंस बन गया है। शामिल होने से पहले उन्होंने कांग्रेस के सामने ये बड़ी शर्त रख दी है। प्रकाश आंबेडकर ने सांसद राहुल



गांधी के निमंत्रण का जवाब देते हुए कहा, आज मुझे राहुल गांधी से उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला। मैंने सशर्त निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और इस तथ्य पर जोर दिया है कि मेरे लिए उनकी यात्रा में शामिल होना मुश्किल होगा क्योंकि वीबीए को अभी तक इंडिया गठबंधन और एमवीए में आमंत्रित नहीं किया गया है। इंडिया और एमवीए में शामिल हुए बिना यात्रा में शामिल होने से गठबंधन की अटकलें लगाई जाएंगी, जो अभी तक साकार नहीं हुई

है। इसलिए, मैंने राहुल गांधी से वीबीए को भारत गठबंधन और एमवीए दोनों के लिए निमंत्रण भेजने का अनुरोध किया है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बस से यह दूरी तय करेंगे। वहीं कुछ प्रमुख जगहों पर पैदल मार्च भी करेंगे। यात्रा मणिपुर में एक दिन में 107 किमी, चार अन्य पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड में दो दिनों में 257 किमी, अरुणाचल प्रदेश में एक दिन में 55 किमी, मेघालय में एक दिन में पांच किमी और असम आठ दिनों में 833 किमी को कवर करेंगे।

कैमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग, 1 कर्मचारी की मौत और 4 घायल



ठाणे: एक रसायन बनाने वाली एक कंपनी में कई विस्फोट हुए। जिसके बाद घटनास्थल पर भीषण आग लग गई। इस दौरान घटना में एक

कर्मचारी की मौत भी हुई है। हादसे में 4 कर्मचारी घायल भी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मृत कर्मचारी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और विस्फोटों का कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख यासीन तडवी ने कहा, यह घटना सुबह करीब 4.30 बजे एक

औद्योगिक इलाके में हुई। कुलगांव-बदलापुर फायर सर्विसेज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी भागवत सोनावणे के अनुसार, फैक्ट्री खारवई एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने कहा कि यूनिट में सिलसिलेवार जोरदार विस्फोट हुए जिससे आग भी लग गई। उन्होंने कहा, कुछ रसायनों से भरे ड्रम फट गए, जिससे सामग्री

बाहर खड़े टैम्पो और वाहनों पर फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप वाहनों में आग लग गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में एक कर्मचारी की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। अंबरनाथ, बदलापुर और उल्हासनगर से चार दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया।



महाराष्ट्र की बल्ले-बल्ले: दावोस में मिला 3.53 लाख करोड़ का निवेश, लाखों युवाओं की नौकरी पक्की...

मुंबई: विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की 54वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही है। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में मंत्रियों व अधिकारियों का समूह भी शामिल हुआ है। डब्ल्यूईएफ कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र को 3.53 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिलेगा। जिससे राज्य में बड़ी संख्या में युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मुताबिक, राज्य ने दावोस में डब्ल्यूईएफ 2024 के दौरान 3,53,675 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। दावोस डब्ल्यूईएफ



सम्मेलन के पहले दिन 16 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार और छह उद्योगों के बीच 1.02 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए। सीएम शिंदे की मौजूदगी में 'महाप्रित' और 'ग्रीन एनर्जी 3000' के बीच 40 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते के तहत राज्य में

सोलर एनर्जी नीति के अनुरूप सोलर एनर्जी पार्क, पवन ऊर्जा, हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किये जायेंगे। पहले चरण में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। सौर, हाइब्रिड एनर्जी और बैटरी एनर्जी भंडारण की मदद से इस क्षमता को 10000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अलावा गुरुवार को ही

2 लाख से अधिक नौकरियां मिलेंगी

वहीं, दूसरे दिन आठ उद्योगों के साथ 2.08 लाख करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जबकि तीसरे दिन 18 जनवरी को छह उद्योगों के साथ 42,825 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, इन एमओयू से राज्य में दो लाख से अधिक नौकरियों के अवसर मिलेंगे।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 'महाप्रित' और हीरो प्यूचर एनर्जी के बीच 8000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

हादसों का सिलसिला जारी... सड़क विकास निगम की उपेक्षा



पनवेल: पनवेल शहर के प्रवेश द्वार खंडेश्वर रेलवे ब्रिज के पास का मोड़ दिन-ब-दिन खतरनाक होता जा रहा है। इस मोड़ पर सड़क विकास निगम की लापरवाही खतरनाक होती जा रही है क्योंकि पनवेल से बाहर निकलते समय लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पनवेल शहर से होकर गुजरने वाले पुराने मुंबई पुणे मार्ग पर पनवेल शहर के प्रवेश द्वार खंडेश्वर रेलवे पुल से पहले थानानाका क्षेत्र में एक तीव्र मोड़ है। इसलिए इस जगह पर चालक वाहन से नियंत्रण खो देते हैं और वाहन बार-बार पलट जाते हैं। सड़क विकास निगम द्वारा इस स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की रेलिंग लगाई गई है। हालांकि, चूँकि

इस स्थान पर सप्ताह में एक बार भारी वाहन पलट जाते हैं, इसलिए रेलिंग वाहनों की गति नहीं झेल पाती, इसलिए बार-बार नई रेलिंग लगानी पड़ती है। इस बिंदु पर एक छोटे से टर्निंग इंडिकेटर के अलावा कोई उपाय नहीं किया गया है, इस इंडिकेटर की दृश्यता बहुत कम है। साथ ही इस मोड़ पर ही एक बड़ा विज्ञापन बोर्ड भी लगाया जा रहा है, जो वाहन चालकों का ध्यान भटका रहा है। गार्डन होटल के सामने ट्रैफिक सिग्नल के तुरंत बाद एक मोड़ आता है। यहां के ड्राइवर तेज गाड़ी चलाते हैं। लेकिन, दो सौ मीटर पर अचानक तीव्र मोड़ आने के कारण चालक वाहन से नियंत्रण खो देता है।

महाराष्ट्र में बनाएगा - 50,000 करोड़ के निवेश से डेटा सेंटर



मुंबई: दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में शामिल अदाणी ग्रुप अब महाराष्ट्र में हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाएगा। अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इसके लिए बुधवार को महाराष्ट्र सरकार के साथ एक मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। समझौते के तहत महाराष्ट्र में 1 गीगावाट की क्षमता का हाइपरस्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए अदाणी ग्रुप 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी की मौजूदगी में टडव पर साइन हुए हैं। कंपनी ने कहा, "यह डेटा सेंटर मुंबई या नवी मुंबई और पुणे

जैसी प्रमुख जगहों पर स्थापित किया जाएगा। यह रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट होगी, जो महाराष्ट्र में ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी। साथ ही इससे 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा।" कंपनी ने आगे कहा कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट ने कुछ ही साल में मुंबई को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम किया है।

मोबाइल फोन पर बात करते समय रेलवे ट्रेक पार करना युवक की जान पर भारी

नवी मुंबई: हाल ही में जुईनगर रेलवे स्टेशन पर एक घटना घटी जहां मोबाइल फोन पर बात करते हुए रेलवे ट्रेक पार करते समय एक युवक की जान चली गई। इस युवक का नाम अनिलकुमार राजकुमार पटेल (26) है और इस युवक का सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अधिकांश नागरिक संचार के साधन के रूप

मुंबई: राज्य के कई आंगनबाड़ियों में बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक अभिनव योजना के तहत 36 हजार 978 आंगनबाड़ियों में सौर ऊर्जा सेट स्थापित करने का निर्णय लिया है। बिजली की कमी के कारण लगभग 36 हजार 978 आंगनबाड़ियों में बिजली की आपूर्ति नहीं हुई। इस मामले को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव



अदिति तटकरे, आयुक्त रूबल अग्रवाल और संबंधित अधिकारियों ने हाल ही में एक बैठक की और इन सभी आंगनबाड़ियों में सौर ऊर्जा सेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इन आंगनबाड़ियों के लिए एक किलोवाट



में मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, हालांकि, कुछ व्यक्तियों को इन मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग करते देखा जाता है। कुछ लोग ईयर फोन लगाकर अपने मोबाइल फोन में

इतने खोए रहते हैं कि उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं रहता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। 25 दिसंबर की सुबह जुईनगर रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही हुआ। तुर्भे निवासी अनिलकुमार राजकुमार 25 दिसंबर की सुबह काम छोड़कर खारघर से तुर्भे जाने के लिए जुईनगर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। वहां से उन्हें तुर्भे जाने के लिए दूसरा प्लेटफार्म लेना पड़ा।

प्रदेश के 37 हजार आंगनबाड़ियों में लगेंगे सौर ऊर्जा सेट!

क्षमता के सौर ऊर्जा सेट लगाए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए राज्य स्तर से ई-टेंडरिंग के जरिये ये सौर ऊर्जा सेट खरीदे जायेंगे। इसके लिए 250 करोड़ रुपये के खर्च की अनदेखी की गयी है।

वेतन बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले चालीस दिनों से हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल से आंगनबाड़ी के बच्चों और महिलाओं पर भारी असर पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठनों ने आंगनबाड़ियों में पर्याप्त सुविधाएं दिलाने, आंगनबाड़ियों और मोबाइल फोन का किराया बढ़ाने सहित कई मांगें की हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने समय-समय पर चर्चा के बाद इनमें से कई मांगों को स्वीकार कर लिया है। कुछ पर सकारात्मक रुख। आयुक्त रूबल अग्रवाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपनी जिम्मेदारी समझने और हड़ताल वापस लेने की अपील की है। सूत्रों ने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए निकट भविष्य में कुछ योजनाएं लागू की जाएंगी।

मुलुंड में धारावी पुनर्विकास परियोजना में स्थानांतरण

स्थल, आवास विभाग
के आदेश...



मुलुंड: आवास विभाग ने शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव और मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल को एक पत्र के माध्यम से मुलुंड में मुंबई नगर निगम की 146 एकड़ जमीन और मुलुंड के जकात नाका में 18 एकड़ जमीन को धारावी पुनर्विकास परियोजना में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। सिंह चहल. सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को एक विशेष परियोजना घोषित कर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना का दर्जा दिया है। धारावी पुनर्विकास परियोजना प्रा. लिमिटेड पात्र निवासियों के लिए मुफ्त घर और लगभग साढ़े तीन से चार लाख अपात्र निवासियों के लिए किफायती किराये के घर बनाएगा।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rookthoklekaninews.com